भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2531

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में डिजिटल ग्राम परियोजना

2531. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल ग्राम परियोजना के अंतर्गत योजनाकृत सभी डिजिटल सुविधाओं से युक्त पूर्ण रूप से तमिलनाडु और देश में क्रियाशील गांवों का ब्यौरा और संख्या कितनी है;

(ख) सभी निवासियों के लिए पर्याप्त इंटरनेट बैंडविड्थ, बिजली और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या महिलाओं, छात्रों और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए डिजिटल सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु विशेष पहल की गई है; और

(घ) कनेक्टिविटी या संसाधनों की कमी का सामना कर रहे गांवों में डिजिटल विभाजन और बुनियादी ढाँचे के अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पसवान)

(क) से (घ): जैसा कि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, देश में दूरदराज के ग्रामीण गांवों और द्वीपों जिनमें वर्तमान में कवरेज की कमी है, को उच्च बैंडविड्थ क्षमता इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)], दूरसंचार विभाग (डीओटी) से वित्त पोषण से कई उपाय और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी प्रदान की जा सके। अक्टूबर-2025 तक; तमिलनाडु में 10,808 ग्राम पंचायतों सहित देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,843 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा दिनांक

04.08.2023 को अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी), भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों (लगभग 42,673 ग्राम पंचायत) में नेटवर्क निर्माण, शेष गैर- ग्राम पंचायत गांवों को उनके संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी हेतु कार्यान्वयन किया जा रहा है।

4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत, अक्टूबर-2025 तक, सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत देश में सेवा रहित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में 22,987 मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उच्च गति इंटरनेट/डेटा संपर्कता प्रदान करने के लिए 10.08.2020 को चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच (2312 किमी) पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल चालू किया गया। दिनांक 03.01.2024 को मुख्य भूमि (कोची) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (1869 किमी) के बीच पनडुब्बी ओएफसी संपर्कता स्थापित की गई। एफटीटीएच और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षद्वीप द्वीपों में 225 किमी ओएफसी नेटवर्क का निर्माण किया गया। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं के त्वरित रोल आउट की सुविधा प्रदान की है।

ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उन्नत संगणन विकास केंद्र और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से विभिन्न आईटी-आधारित समाधान डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किए हैं। डिजिटल अंतर को कम करने और अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल सुशासन समाधान ऑफ़लाइन क्षमताओं, दिव्यांग अनुकूल प्लेटफार्मों और बहुभाषी सुविधाओं सहित सरल उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ विकसित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि इन समाधानों तक पहुंच इंटरनेट से जुड़े क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूरस्थ या गैर-जुड़े क्षेत्रों तक भी है।

*****